विचार बिन्दु

अवसर तुम्हारा दरवाज़ा एक ही बार खटखटाता है। –कहावत

भजनलाल सरकार का तीसरा बजट: हर राजस्थानी के सपनों को पूरा करने वाला बजट है

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य विधान सभा में वर्ष 26-27 का सालाना बजट प्रस्तुत करते हुए आशा व्यक्त की है कि यह बजट हर राजस्थानी के सपनों को पूरा करेगा। यह एक बहुत ही संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। इस बार बजट का कुल आकार 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये रखा गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 41.39 प्रतिशत अधिक है, जो राजस्थान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह बजट पिछले साल की तुलना में करीब 10 फीसदी ज्यादा है। इस बजट में राज्य सरकार ने किसानों, महिला सशक्तिकरण, युवाओं और रोजगार को फोकस में रखा है। बजट प्रदेश की जनता के प्रति सरकार के प्रत्येक दायित्व को पूरा करने का संकल्प दर्शाता है। इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का स्पष्ट दृष्टिकोण है।

ये विकसित भारत 2047 के संकल्प को गति देता देगा। विकसित राजस्थान को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति की अहम भूमिका को सरकार ने सेवा, समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है। इस बजट में गरीबों और किसानों का कल्याण, वंचितों का सम्मान और महिलाओं और हर वर वर्ग का उत्थान शामिल है। यह बजट प्रधान मंत्री के सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को सार्थक करेगा। यह विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक शानदार बजट है। बजट में समाज के सभी वर्गों को कमोवेश राहत प्रदान की गई है।

वित्त मंत्री ने आम आदमी के कल्याण की विभिन्न घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए अपनी सरकार का मंतव्य भी स्पष्ट कर दिया। यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और सभी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। बजट में समाज के सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है। यह विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने वाला एक बेहतरीन बजट है। सरकार का दावा है कि यह बजट सभी वर्गों का सम्मान करते हुए लोगों का जीवन आसान बनाने पर केंद्रित है।

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने जहां तारीफों के पुल बांधे वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है।

बजट में आम तौर पर फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरे, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भागीदार कैसे बने, इसकी बहुत मजबूत नींव रखता है। वित्त मंत्री ने अपने तीन घंटे के भाषण में हर सेक्टर को छूने का प्रयास किया है। बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में सड़कों के लिए 1800 करोड़ रुपए बजट प्रस्ताव, ब्लैक स्पॉट्स सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च होंगे, 42 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का विस्तार किया जायेगा। बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए हाईपावर कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संचालन के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को खेल किट और 'जादुई पिटारा' उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों को मजबूती देने की दिशा में माना जा रहा है। शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने की 32 हजार करोड़ रुपये की परियोजना जल्द शुरू होगी। बीसलपुर की दायीं मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से फव्वारा सिंचाई प्रणाली लागू की जाएगी। अगले वर्ष 50 हजार सोलर पंप लगाने पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 8000 डिग्गियों का निर्माण और 36 हजार फार्म पोंड के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिससे 80 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजमार्गों पर विकसित की जाएगी वे साइड एमेनिटीज। लॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ का बजट,, के लिए 920 करोड़ का प्रावधान। 600 ट्यूबवेल और 120 नए हैंड पंप लगाए जाएंगें। राजधानी जयपुर में 10 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस, मोबाइल वॉटर टेस्टिंग लैब होगी शुरू होंगी। 1050 तकनीकी कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। नॉनपैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ दिए जायेंगे। 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस की घोषणा की गई है। वर्षा जल निकासी और बाढ़ सुरक्षा के लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपए और सड़क सुधार सुधार पर 2700 करोड़ खर्च होंगे। अजमेर में 200 करोड रुपए के ड्रेनेज सिस्टम कार्य होंगे। 2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती का ऐलान। प्रदेश में बिना डॉक्युमेंट वाले मरीजों को भी फ्री इलाज़ मिलेगा। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि करीब 130 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कई काम किए जाएंगे। 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और रोजगार के पर्याप्त अवसर देने के लिए जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है।

बजट में आम तौर पर फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरे, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भागीदार कैसे बने, इसकी बहुत मजबूत नींव रखता है। वित्त मंत्री ने अपने तीन घंटे के भाषण में हर सेक्टर को छूने का प्रयास किया है। बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं।

भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु 1020 करोड़ का प्रावधान। विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की होगी स्थापना। ट्रांसफार्मर, फीडर और सब स्टेशन की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। अजमेर डिस्कॉम के ग्रिड को किया जाएगा एआई इनेबल्ड। एनटीए के तर्ज पर राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना की घोषणा। 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत। ऑनलाइन सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का भी होगा निर्माण। नगर निकायों में 4 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को 10 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा मिलेगी। बांधों के डाउन स्ट्रीम में लगेंगे सायरन, खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए।

–अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

आम आदमी को राहत व प्रदेश के विकास को आगे ले जाने वाला बजट

सी.ए. शंकर अग्रवाल

आर्थिक विशेषज्ञ सी.ए. शंकर अग्रवाल ने राज्य बजट को आम आदमी को राहत व अनेक विकास योजनाओं के साथ-साथ भविष्य के विकसित राजस्थान का नक्शा प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने हर वर्ग चाहे किसान हो या व्यापारी, महिला, युवा, उद्यमी सभी वर्गों का ध्यान रखकर बजट प्रस्तुत किया है। गांव गरीब और किसान के साथ-साथ उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों को प्रगति पथ पर ले जाने का सरकार का इरादा साफ झलकता है। राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी है। अत: पर्यटन को बढ़ावा देने की अनेक घोषणाऐं राज्य के विकास का आधार बनेगा। महिला सशक्तिकरण हेतु लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत सोलह लाख लखपति दीदी, व्यवसाय हेतु मिलने वाला ऋण एक से बढ़कर डेढ़ लाख रूपये करना महिलाओं को प्रशिक्षण व बच्चों हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तीन से छ: वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा हेतु पंजीयन करना। किसानों को 25000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण तारबंदी हेतु दस से घटाकर सात किसानों की संख्या 2098 ग्राम पंचायत स्तर पर बर्मी कम्पोज खाद केन्द्र बनाये जायेंगे। 500 सोलर पम्पस पर 1500 करोड़ का खर्च, हरियाणा से किसानों को पानी उपलब्ध करवाना एवं 2.50 लाख किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करवाने की घोषणा निश्चित ही प्रदेश के किसानों की हालत में सुधार के साथ-साथ राजस्थान कृषि क्षेत्र में अग्रणी होगा। अभी भी राजस्थान की कृषि का देश की औसत जीडीपी में योगदान 27 प्रतिशत है जो देश के अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा है। राजस्थान का पहला बजट 7 अप्रेल 1952 को राज्य विधानसभा में नाथूराम मिर्धा ने वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें 1605.17.लाख का राजस्व व 1620.17 लाख का खर्च था। आज हमारे बजट में 325740.14 करोड़ का राजस्व एवं 350054.07 करोड़ का राजस्व व्यय है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वर्षों तक पिछडा राजसीन कहलाने का कलंक राज्य की जनता ने झेला है।

आज हमारा राज्य पिछड़ा व बीमार राज्य से निकल कर विकासशील राजस्थान की अग्र श्रेणी में आ गया है। यह हमारे सभी के प्रयासों व सरकार की इच्छाशक्ति का परिणाम है कि आज 16430 किमी. की सड़कों का जाल राजस्थान में बिछा है, कहीं भी जायें सड़कों को देखकर राजस्थान की प्रगति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

राज्य की जीडीपी का देश की जीडीपी में 5.18 प्रतिशत योगदान है। किसी समय में हमारी जीडीपी दो से ढ़ाई प्रतिशत तक सीमित थी। आज राज्य की जीडीपी में 46 प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्र का है जिसमें पर्यटन सेवा, खनिज उद्योग क्षेत्र का बड़ा योगदान है। इसके अलावा 27 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र व 27 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का योगदान है। जहां राज्य में प्रवासी राजस्थानी उद्योग लगाने से डरते थे, क्योंकि यहां आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बिजली-पानी का अत्यन्त अभाव था। राजस्थान जहां किसी समय में 3952 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था, वहीं आज 6739 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। जल आपूर्ति हेतु अनेक योजनाओं पर काम जारी है। अत: यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। यह बहस का विषय हो सकता है कि किस सरकार ने कितना विकास कर राज्य को आगे बढ़ाया है। आज वित्त मंत्री ने राजस्थान की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुये हर क्षेत्र को बिना नये कर लगाये, अतिरिक्त बजट देना व अनेक विकास योजनाओं की घोषणा निश्चित ही राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

–सी.ए. शंकर अग्रवाल

आर्य समाज के संस्थापक "स्वामी दयानन्द सरस्वती"

12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानन्द सरस्वती की 202वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन

डॉ. जे.के. गर्ग,

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान विचारक, समाज सुधारक थे। उनका जन्म गुजरात के टंकारा में ओडीचय परिवार के अंदर 12 फरवरी 1824 को हुआ था, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' का नारा दिया और मूर्तिपूजा, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान और हिंदी और स्वराज्य के लिए कार्य किया। उन्होंने सत्य की खोज में युवावस्था में ही घर छोड़ दिया था।

वेदों और वैदिक दर्शन के प्रकांड विद्वान

10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया और महिला शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश उनका प्रसिद ग्रन्थ है। उन्होंने वेदभाष्य, और संस्कार विधि की रचना की। उन्होंने ही स्वराज्य का नारा सबसे पहलें 1876 में दिया। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में उनका निधन हुआ।

स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे

स्वामी दयानंद ने अंधविश्वासों को मिटाकर वैदिक ज्ञान को पुन: स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचारों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी समाधि अजमेर में है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी जी यज्ञ पर विशेष जोर देते थे। आर्य समाज के अनुयायी देश के विभिन्न हिस्से में निवास करते हैं।

–डॉ. जे.के. गर्ग, पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

एक प्रगतिशील मुस्लिम राष्ट्र: ओमान

प्रो .कैलाश सोडाणी

मेरी विद्यार्थी प्रोफेसर कनिज फातिमा, जो पिछले 16 वर्षों से ओमान की निजवा विश्वविद्यालय में शिक्षक है, के निमंत्रण पर मुझे ओमान यात्रा का अवसर मिला। विश्वविद्यालय में लगभग 10000 विद्यार्थी एवं 400 शिक्षक हैं। जिनमे से 50 प्रतिशत शिक्षक अन्य देशों से हैं। उच्च शिक्षा के मामले में ओमान काफी पीछे था। सरकार एवं जनता दोनों में जागरूकता आयी है। ओमान में लगभग 29 विश्वविद्यालय हैं, उनमें निजी और सरकारी दोनों शामिल है। सरकार बहुत ही आधुनिक एवं डिजिटल व्यवस्था से पूर्ण श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त विश्वविद्यालय बना रही है। यही कारण है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ओमान के 10 विश्वविद्यालय शामिल है। निजवा विश्वविद्यालय ओमान का सर्वोच्च रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय हैं।

विश्वविद्यालय में क्लास-रूम टीचिंग के प्रति बहुत गंभीरता है। विद्यार्थियों की उपस्थिति लगभग 90 प्रतिशत रहती है। पुस्तकालय बहुत ही धनाढ्य एवं आधुनिक है। प्राय: अध्यापक एवं छात्र-छात्राएं कैफेटेरिया में ही लंच लेते हैं, जहां बहुत ही उम्दा किस्म का भोजन न्यूनतम दरों पर उपलब्ध है। पूरा विश्वविद्यालय ही वातानुकूलित है एवं कैंपस में पूर्ण शांति का माहौल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुस्लिम देश के विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या 90 प्रतिशत है। लडकियों में उच्च शिक्षा के प्रति यह जागरूकता ओमान के उज्जवल भविष्य की गारंटी प्रदान करती है। साथ ही छात्रों में उच्च शिक्षा के प्रति कमजोर मानसिकता चिन्ता का विषय है।

ओमान एक शांतिप्रिय, सुरक्षित एवं प्रगतिशील मुस्लिम राष्ट्र है। जहां सुल्तान के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए प्रजातांत्रिक व्यवस्था का लाभ भी ले रहे हैं।

आबादी लगभग 54 लाख है, जिसमें से 45 प्रतिशत प्रवासी हैं। प्रवासी समुदाय में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है, जो लगभग 9 लाख है। ओमान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,09,500 वर्ग किलोमीटर है। अपनी प्राचीन संस्कृति, पारंपरिक वास्तुकला, रेगिस्तानी नजारों और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है। निजवा का म्यूजियम बहुत ही सराहनीय है। जहाँ ओमान के पुरातन से लेकर विकास की वर्तमान यात्रा को डिजिटल व्यवस्था से प्रदर्शित किया गया है। भारत के बड़े शहरों में भी इस प्रकार के म्यूजियम बनाने की आवश्यकता है। पर्यटन और मेहमान-नवाजी देश की पहचान है। देश की अर्थव्यवस्था तेल एवं गैस पर निर्भर है।

देश की शत-प्रतिशत आबादी को बिजली, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही मजबूत एवं खूबसूरत सडके हैं। लोगों में उच्च स्तर का ट्राफिक सेंस है इसलिए गाडियां 125-150 किलोमीटर की रफ्तार से बिना हॉर्न की आवाज के दौड रही है। पूरे देश में पार्किंग व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है ।

पूरा देश स्वच्छ है। नागरिक स्वच्छता एवं ट्राफिक व्यवस्था के प्रति बहुत ही गंभीर एवं अनुशासित हैं । कानून की पालन करना उनके जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है । नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा है। लोग प्राय: दिन में मकान और दुकान पर ताला ही नहीं लगाते हैं। आप कभी कोई चीज कहीं भूल जाते है, दो-चार दिन बाद भी वह वस्तु वहीं मिलती है।

भारत और ओमान के मध्य अच्छे संबंध है। 2024 में दोनों देशों के मध्य 10.61 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत के निर्यात 4.06 अरब डॉलर के मुकाबले आयात अधिक है, जो 6.55 अरब डॉलर है। कुछ दिनों पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान जो समझौते हुए उसके आधार पर अगले पाँच वर्षों में दोनों देशों का व्यापार 20 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। पिछले 15 वर्षों से रह रहे भारतीय व्यापारी श्री मोइज के अनुसार ओमान में व्यापार करना बहुत ही सहज है। एक बार जो हिंदुस्तानी यहां आ गया, वह यहां के सौहार्दपूर्ण वातावरण में रम-बस जाता है।

इस यात्रा में मेरे एक और विद्यार्थी से मुलाकात हुई। श्री अशोक पुरोहित जो पत्रकार है और ओमान टाइम्स में सह-संपादक है, पिछले 26 वर्षों से ओमान में ही कार्यरत है। भारत एवं ओमान के श्रेष्ठ संबंधों पर चर्चा के दौरान एक बहुत अच्छे वाकिये से वाकिफ करवाया। 1996 में भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट पति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ओमान यात्रा पर पधारे। ओमान के सुल्तान (राष्ट्रपति) काबूस बिन सईद का अध्ययन-अध्यापन भारत में हुआ था। डॉ. शंकरदयाल जी उनके शिक्षक थे। सुल्तान काबूस ने एक विद्यार्थी की हैसियत से अपने शिक्षक का भाव-भीना ऐतिहासिक स्वागत किया । डॉ. शर्मा हमारे सुल्तान के शिक्षक है, इसी भावना से संपूर्ण ओमान में वहाँ के नागरिकों ने सडक के दोनों ओर खड़े होकर डॉ. शंकरदयाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया ।

–प्रो .कैलाश सोडाणी,
पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

राशिफल गुरूवार 12 फरवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 1:42 तक, हर्षण योग रात्रि 3:06 तक, विष्टि करण दिन 12:23 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:42 से धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा दिन 12:23 तक है। आज फाल्गुनी संक्रांति सूर्य कुम्भ में रात्रि 4:09 पर प्रवेश करेगा। आज महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:33 तक, चर 11:18 से 12:41 तक, लाभ-अमृत 12:41 से 3:27 तक, शुभ 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:10, सूर्यास्त 6:12

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात मन:स्थिति में सुधार होगा।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

ग्रामीण भारत को विकसित बनाने की संकल्पना पूर्ण करने में मददगार होगी वीबी-जी राम जी

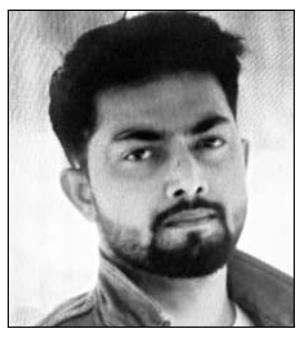

खेमचन्द बैनीवाल

वीबी-जी राम जी- विकसित भारत जिसका पूरा नाम रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) है, ग्रामीण विकास ढांचे को मजबूत बनाने का संकल्प है। यह विकसित भारत 2047 के केन्द्रीय बिन्दुओं युवा, किसान, महिला और गरीब को सशक्त करने का रोडमैप है। गरीब और किसान को सीधा कनेक्ट करने वाली यह योजना जरूरतमंद ग्रामीण आबादी विशेषकर गरीब(उसे ज्यादा जरूरत है) को पर्याप्त रोजगार की गारंटी देती है और किसान को खाली समय में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के साथ ही व्यवस्था करती है जिससे पीक सीजन में श्रम की इतनी अनुपलब्धता न हो जाए कि खेती घाटे का सौदा हो जाए या हमारी खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए। इसके साथ ही यह भारतीय कृषि को परोक्ष रूप से वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है।

यह योजना हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की मजदूरी की वैधानिक गारंटी देती है, ग्रामीणों का सशक्तीकरण करती है, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख की ग्राम स्वराज और ग्राम विकास की संकल्पनाओं को साकार करने का रास्ता तैयार करती है।

छीजत पर रोक, एआई टूल्स का अपयोग कर गड़बड़ी की सम्भावना करेंगे शून्य-

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिया, विशेषकर विपरीत मौसम के समय ग्रामीण आबादी को बीमा जैसे सुविधा दी लेकिन भविष्य के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निर्माण करने में उतनी सफल नहीं हो पायी और इसी बिन्दु पर वीबी-जी राम जी जैसी योजना की आवश्यता महसूस की गई।

नई योजना का फोकस जल सुरक्षा और जल संरक्षण पर है जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विकास और बाढ़ बचाव कार्य भी शामिल हैं। इससे प्रत्यक्ष रूप से किसान व परोक्ष रूप से समूची ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा।

यह योजना 'विकसित ग्राम पंचायत' संकल्पना को साकार करने के लिए 'पीएम गति शक्ति' के साथ एकीकृत करने का स्वप्न बुनती और साकार करती है ताकि ग्राम पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिससे सड़क बनने के बाद पाइपलाइन के लिए सड़क नहीं तोड़नी पड़े या इकॉलोजी सिस्टम को हानि पहुंचाने वाला या नदी बहाव में रूकावट ड़ालने वाला जल संरक्षण ढांचा स्वीकृत या निर्मित न हो।

योजना का लाभ समय पर मिले और पूरा मिले, इसके लिए व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से सुशासन, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को आधुनिक किया गया है। इसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, जीपीएस या मोबाइल-आधारित कार्यस्थल निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम , डैशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण, बेहतर और नियमित ऑडिट तथा धोखाधड़ी-जोखिम न्यूनीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) का उपयोग शामिल करने की परिकल्पना है।

समय पर भुगतान, समय पर रोजगार नहीं तो बेराजगारी भत्ता-

दैनिक मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या असामन्य स्थिति में पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष में बुआई तथा कटाई की चरम कृषि ऋतुओं को कवर करने वाली कुल साठ दिनों की ऐसी अवधि को अग्रिम अधिसूचित करेगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कार्य नहीं किए जाएंगे। इससे किसानों को अपने खेतों में मजदूरी की कमी नहीं होगी व किसान-मजदूर सभी लाभ में रहेंगे। यदि योजना के अंतर्गत रोजगार आवेदक को आवेदन प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या जिस तिथि से रोजगार मांगा गया है, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो वह इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

विकास और योजना की धुरी है ग्राम पंचायत-

ग्राम पंचायत परिवार पंजीकरण एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने, आवेदन लेने, मास्टर रोल जारी करने, रोजगार आवंटन करने का कार्य करेगी। ग्राम सभा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करेगी जो ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करती है।

इस योजना में विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का प्रावधान है। यह एकल महिला, दिव्यांग, साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, मुक्त बंधुआ मजदूर, विशेष श्रेणी के जनजातीय समूह के व्यक्ति हो व ट्रांसजेंडर को उपलब्ध होगा। यह कार्ड सामान्य कार्ड से अलग रंग का होगा, जो उस श्रमिक का कार्य मूल्यांकन और कार्यस्थल सुविधाओं में विशेष संरक्षण सुनिश्चित करेगा। न्यूनतम 10 मजदूर उपलब्ध होने पर नया कार्य शुरू होगा, वनीकरण कार्यों में इस संख्या में छूट रहेगी।

–खेमचन्द बैनीवाल,
सहायक लेखा अधिकारी,
जिला परिषद, जयपुर।

उत्तर-पश्चिम रेलवे ने उच्चतम राजस्व प्राप्त किया

जोधपुर, (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2025-26 में टिकट चेकिंग में अब तक का उच्चतम राजस्व प्राप्त किया है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन पिछले सभी रिकॉर्डों को पार कर गया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे नें टिकट चेकिंग में इस वित्त वर्ष 2025-26 में 9 फरवरी तक टिकट चेकिंग से 63.50 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त किया है जोकि पिछले वर्ष इस अवधि में प्राप्त टिकट चेकिंग राजस्व की तुलना में 27.01 प्रतिशत अधिक है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन पिछले सभी रिकॉर्डों को पार कर गया है। 63.50 करोड़ रूपए का यह राजस्व उत्तर पश्चिम रेलवे के पिछले उच्चतम वार्षिक राजस्व 63.22 करोड़ रूपए (वित्त वर्ष 2023-24) के आंकड़े को 50 दिन पहले पार कर चुका है। अमित सुदर्शन ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए टिकट चेकिंग अभियान के साथ यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। टिकट चेकिंग के लिए विशेष योजना बनाई जाती है। इसके लिए विभिन्न रेलखण्डों में टिकटों की बिक्री, फील्ड स्टॉफ के फीडबैक तथा रेल मदद पोर्टल की समीक्षा कर टिकट चैकिंग की योजना बनाई जाती है। इस से ना सिर्फ रेल राजस्व में वृद्धि हो रही है, बल्कि यात्रियों की शिकायतों में कमी और रेल उपयोगकर्त्ताओं की संतुष्टि में भी वृद्धि हो रही है।